premium rates currently offered by the LIC, to consider whether any revision is called for and if such revision is warranted to advise the premium bases and consequential measures to be taken to ensure equity among policy holders. The Committee has since submitted its detailed report and the same is at present under consideration in the LIC.

Replacement of Sales Tax by Central Excise

888 SHRI S R DAMANI :
SHRI BEDABRATA BARUA :
SHRI BHAGIRATH BHANWAR :
SHRI ARJUN SINGH BHADORIA :

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to replace the Sales Tax by Central Excise ;

(b) if so, the salient features of the scheme ; and

(c) whether any commonly acceptable formula has been worked out with the State Governments ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) to (c). The question of extending the scheme of replacement of sales tax by additional excise duties to some essential commodities like cement medicines vanaspati and petroleum products, as recommended by the Indirect Taxation Enquiry Committee, was last considered at a meeting of Chief Ministers of States held on 19th and 20th May, 1979 The proposal was objected to by a large majority of the States As levy of tax on sales or purchases of goods taking place within a State is a State subject of taxation under the Constitution, it cannot be replaced by excise duty without the concurrence of the State Governments

Periodic Stock-taking of confiscated Goods

889. SHRI S. R. DAMANI
SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether any periodic stock-taking has been carried out of confiscated goods and when;

(b) what is the their total value and whether proper accounts have been maintained;

(c) whether there have been reports of any thefts from the godowns; and

(d) whether any revised procedure for the storage and disposal of confiscated goods is under the consideration of Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) Yes, Sir. According to reports received by Government, stock-taking of seized and confiscated goods stored in Customs godowns has been conducted periodically during the last three years.

(b) Yes, Sir The total value of seized/confiscated goods stored in customs godowns as on 31-3-1979 was about Rs 59.75 crores.

(c) Yes, Sir.

(d) The procedure prescribed in 1961 in regard to proper storage of seized/confiscated goods has been found to be adequate However, the procedures for disposal of these goods were reviewed and revised instructions regarding the manner of disposal of different categories of these goods were issued in May, 1978 In order to accelerating the pace of disposal of seized/confiscated goods ripe for disposal the following additional measures were introduced recently

(i) Sale of some items like synthetic textiles electronic goods and other miscellaneous items to the National Consumers Cooperative Federation for disposal to consumers through Cooperative Consumers Societies Super Bazars etc

(ii) Sale of the above items to the military and para military organisation for use of their personnel

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य किया जाना

890. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या वित्त प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जून के महीने के दौरान रिजर्व बैंक आफ इंडिया के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य करने के आंदोलन के फलस्वरूप बैंक का लगभग सारा काम अस्त-व्यस्त हो गया था जिससे वाणिज्य, व्यापार और उद्योग को भारी घाटा उठाना पड़ा ,

(ख) यदि हां, तो तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें क्या थीं जिसके कारण उन्हें नियमानुसार कार्य करने के लिये मजबूर होना पड़ा तथा क्या सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने हेतु इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता की है और यदि हां, तो इस वार्ता का क्या परिणाम निकला है, और

(ग) रिजर्व बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों के मामले को लेकर हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं इसे देखते हुये क्या सरकार का विचार बैंकिंग सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों की मांगें वेतनमानों के संशोधन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्तों और सेवा शर्तों में सुधार से संबंधित हैं। समझौता कार्रवाई मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के तत्वावधान में हुई थी। कोई समझौता नहीं हो सका। मुख्य श्रम आयुक्त की असफलता की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस विवाद का न्याय निर्णय के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का सौंप दिया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (सेवाये अनिवार्य रखना) अध्यादेश के अधीन जारी किये गये आदेश के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक में हड़ताल प्रतिषिद्ध कर दी गई है।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स में वाणिज्यिक विमान चालकों की कमी

891 **श्री अनन्त राम जायसवाल** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में वाणिज्यिक विमान चालकों की अत्यधिक कमी है जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों एयर लाइन्स की सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां तो 31 दिसम्बर, 1974 से 31 दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में पृथक्पृथक कितने वाणिज्यिक विमान चालक कार्य कर रहे थे ,

(ग) वाणिज्यिक विमान चालकों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है , और

(घ) वर्ष 1979-80 में एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स द्वारा पृथक् पृथक कितने अतिरिक्त विमान/एयर बस किराये पर लेने अथवा खरीदने का विचार है और इसके लिये कितने अतिरिक्त विमान चालक चाहियें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) जी नहीं, इंडियन एयरलाइन्स के पास अपने चालू परिचालनों के लिये वाणिज्यिक विमानचालकों की कोई कमी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1980-81 की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये इंडियन एयरलाइन्स ने प्रशिक्षु विमानचालकों की भर्ती के लिये मार्च, 1979 के दौरान एक विज्ञापन जारी किया है तथा चयन किया जा रहा है।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स वर्ष 1981 तक इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में वृद्धि करने के लिये विमान प्राप्ति कार्यक्रम के अनुसार, इंडियन एयरलाइन्स ने सात बोइंग 737 विमानों (जिनमें नष्ट हुये विमान के बदले में लिये जाने वाला एक विमान भी सम्मिलित है) तथा दो एयरबस ए-300 बी 2 विमानों की खरीद के लिये आदेश दे दिये हैं। 1981 में परिचालनों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त विमानचालकों की संख्या लगभग 60 है।

एयर इंडिया

एयर इंडिया ने चार बी 747 विमानों की खरीद के लिए (जिनमें 1-1-78 को दुर्घटना में नष्ट हुये विमान के बदले में लिया जाने वाला एक विमान भी सम्मिलित है) आदेश दे दिये हैं। इन विमानों की डिलीवरी मार्च 1980 तक होनी है।

जहां तक अतिरिक्त विमानचालकों की आवश्यकताओं का संबंध है यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जहां तक प्रश्न के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में एयर इंडिया से संबंधित सूचना का संबंध है सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Export of Rice

892 SHRI P RAJAGOPAL NAIDU Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether rice has been exported to other countries this year,

(b) if so, how much, and

(c) from which States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) (a) Yes, Sir.

(b) During 1978-79, 67800 MT of Basmati Rice was exported During April-May 1979 a quantity of 3,952 MT of Basmati Rice was exported 10 000 tonnes of rice other than Basmati have been exported and 30,000 tonnes were contracted for export